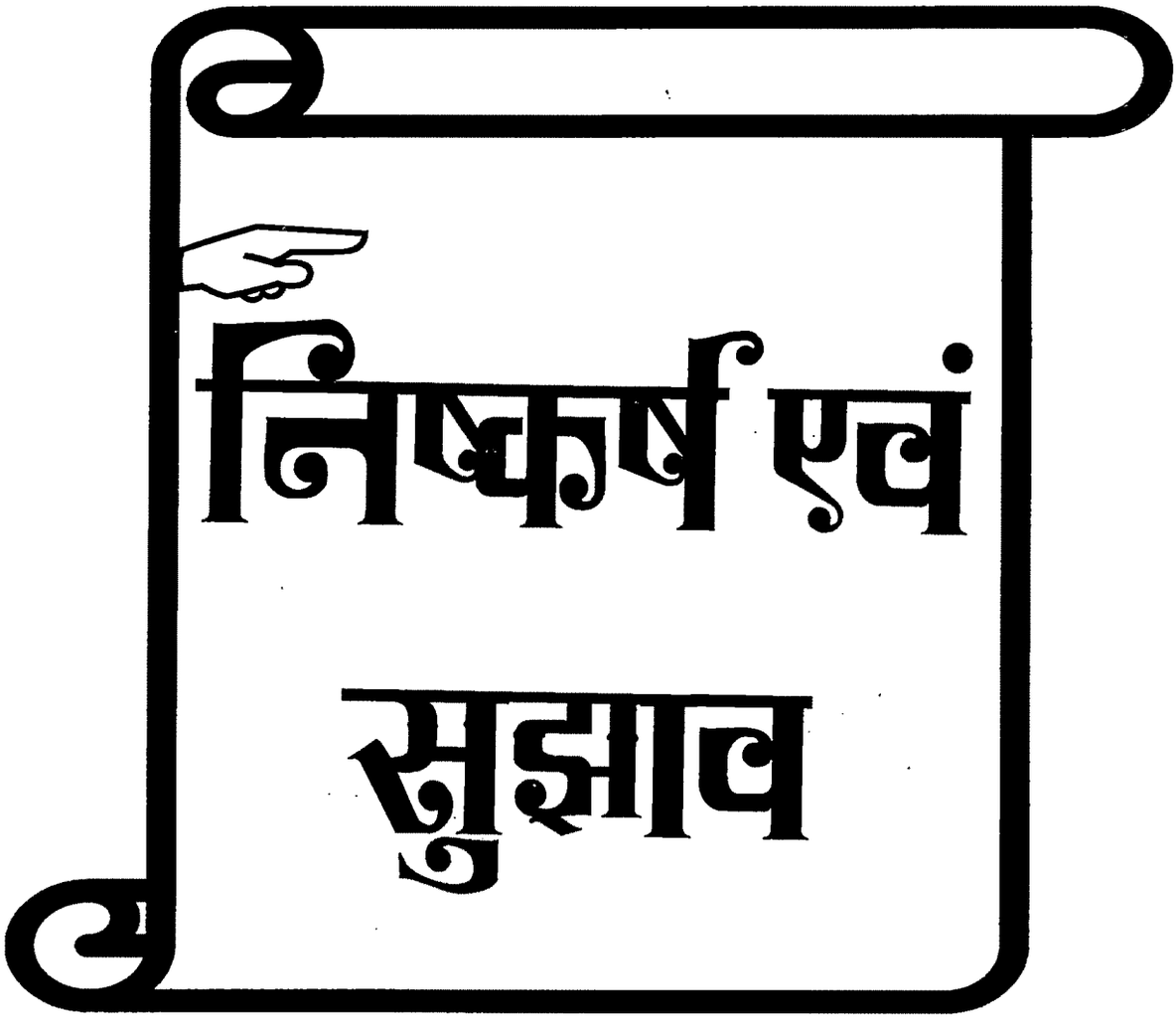

निष्कर्ष एवं सुझाव

शोध निष्कर्ष, शोध एवं भावी विकास के लिए सुझाव तथा शैक्षिक महत्व

शोध निष्कर्ष :-

जनपद में माध्यमिक स्तरीय शिक्षा के बारे में अध्ययन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि शिक्षा के माध्यमिक स्तरों का प्रसार तो हो रहा है पर गुणवत्ता में कमी आ रही है। गुणवत्ता में कमी आने का कारण विशेष रूप में सरकारी तन्त्र एवं जनता की या तो उपेक्षात्मक दृष्टि हो या वे इस दिशा में कुछ कर सकने के लिए अपने को असमर्थ पा रहे हैं। यह जौनपुर जनपद ही नहीं समस्त देश की स्थिति, उसका प्रभाव जौनपुर जनपद पर भी पड़ रहा है। ये तो सामान्य कारण है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के अध्ययन के फलस्वरूप शोधकर्ता निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचा था।

1. माध्यमिक विद्यालयों की संख्या बढ़ी है।
2. माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों का पंजीकरण बढ़ा है।
3. जनपद में माध्यमिक स्तर पर सरकार द्वारा किया गया प्रयास जारी है।
4. जनपद के प्रबुद्ध तथा धनी वर्ग अपनी माध्यमिक संस्थायें चलाकर शिक्षा का प्रकाश फैला रहे हैं।

5. ग्रामीण क्षेत्रों में भी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक संस्थायें बढ़ी हैं।

6. माध्यमिक स्तर पर पहले से पूर्व, माध्यमिक विद्यालयों तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या बढ़ी है।

7. माध्यमिक संस्थाओं में कुछ स्ववित्तीय और पहले की वित्तीय संस्थायें आज और भी मजबूत हुई हैं।

8. जनसंख्या वृद्धि के साथ शिक्षा का स्तर भी बढ़ा है।

9. उच्च शिक्षा संस्थायें भी सर्वांगीण विकास हेतु प्रयासरत हैं।

10. जनपद जौनपुर में शिक्षा का प्रसार द्रुत गति से हुआ, परन्तु गुणात्मक शिक्षा में ह्रास हुआ।

11. बालिकायें भी शिक्षा की ओर जागरुक हुई और उन्हें छात्रों की तुलना में अधिक सफलता मिली।

12. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा का प्रसार व्यापक नहीं हुआ।

13. प्राथमिक शिक्षा का स्तर गिरता रहा, जिससे उच्च कक्षाओं का स्तर भी प्रभावित हुआ।

14. शिक्षा को व्यवहारिक और जीवनोपयोगी नहीं बनाया गया।

15. आर्थिक दृष्टि से जनपद के पिछड़े होने के कारण विद्यालयों में समुचित भवन, साज, सज्जा एवं समुचित उपकरणों का अभाव।

16. शिक्षा में सैद्धान्तिक पक्ष पर जोर दिया जाता है। रचनात्मक कार्य पूर्णतया उपेक्षित रहता है। खेलकूद, सांस्कृतिक क्रिया–कलाप नहीं के बराबर है।

17. कुछ शिक्षण संस्थायें परीक्षा में अनैतिक व्यापार चलाती हैं, जिससे छात्रों में भ्रष्टाचार का बीज पनप रहा होता है।

18. सबके लिए शिक्षा का सुलभ होना जिसके कारण प्रथम पीढ़ी के छात्रों के शैक्षिक स्तर में न्यूनता।

19. जनसामान्य में शिक्षा के प्रति चेतना एवं अभिरुचि का अभाव।

20. राजनीतिज्ञों द्वारा शिक्षा की स्थिति को महत्व न देना तथा उनके द्वारा शिक्षाविदों की उपेक्षा।

21. चारित्रिक दृष्टि से अभिभावकों में नैतिकता का अभाव एवं कर्तव्य की उपेक्षा।

22. जनपद जौनपुर की शैक्षिक पृष्ठभूमि उर्वर रही है। मध्यकाल में यह इस्लामिक शिक्षा का केन्द्र रहा। अरबी, फारसी, उर्दू के धुरन्धर विद्वानों का जौनपुर केन्द्र था। संस्कृत, हिन्दी के ख्याति प्राप्त कवियों की यह भूमि रही। इसका व्यापक प्रभाव यहाँ के जनमानस पर पड़ा। आधुनिक शिक्षा का प्रकाश फैलते ही जनमानस जागरूक हो उठा। कवियों, लेखकों, साहित्यकारों एवं विचारकों द्वारा यहाँ की धरती गौरवान्वित हुई।

23. बालिकाओं की शिक्षा की संतोषजनक स्थिति नहीं है। बालिकाओं के विद्यालयों की संख्या कम है।

24. दलित वर्ग और पिछड़ी जातियों में शिक्षा का व्यापक प्रसार नहीं हुआ।

25. तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था विश्वविद्यालय में तथा पालिटेक्निक

और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में की गई, परन्तु जनपद की अपेक्षाओं को देखते हुए यह अपर्याप्त है। तकनीकी शिक्षा के अधिक विस्तार की आवश्यकता है।

26. जनपद जौनपुर की भूमि कृषि के लिए उपयुक्त और उर्वर है। फल–सब्जियाँ यहाँ प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होती हैं। इन पर आधारित उद्योग यहाँ खोले जा सकते हैं। इसके लिए उपयोगी तकनीकी प्रशिक्षण के विद्यालय खोले जायं तो शिक्षित नवयुवकों के रोजगार की संभावनायें बढ़ सकती हैं।

27. निःसन्देह जनपद में पब्लिक स्कूल अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, किन्तु अच्छी शिक्षा की ओट में ये विद्यालय जनता का भरपूर शोषण कर रहे हैं। जहाँ पर उदारचेता लोग समाज सेवा की भावना से विद्यालय चलाते थे, वहीं ये शिक्षण माफिया व्यवसाय चला रहे हैं और राष्ट्र की समाजवादी व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहे हैं। शासन को इनके शोषण पर अंकुश लगाना चाहिये। साथ ही साथ सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों का वातावरण भी चुस्त–दुरूस्त बनाना होगा, ताकि विद्यार्थी पब्लिक विद्यालयों के व्यमोह में न उलझें।

28. कुछ संस्कृत पाठशालायें और इस्लामिक मकतब और मदरसे भी जनपद में चल रहे हैं, जिन पर रूढ़िवादिता और साम्प्रदायिक संकीर्णता का आरोप लगाया जाता है। शासन को चाहिए कि इन पर भी निगरानी रखें और आधुनिक विषयों का वहाँ भी समावेश

किया जाय, जिससे राष्ट्र के धर्म निरपेक्ष प्रजातान्त्रिक मूल्यों की रक्षा हो सके।

29. सभी बालकों का बौद्धिक स्तर मानसिक अभिरुचियाँ समान नहीं होती। कुछ बालक मन्द बुद्धि या अति सामान्य बुद्धि के होते हैं, जो क्लिष्ट सैद्धान्तिक विषयों की अवधारणा और अमूर्त चिन्तन नहीं कर सकते, किन्तु उनमें शिल्प, कला कौशल, संगीत, खेल कूद, कृषि, बागवानी, फल संरक्षण जैसे मूर्त विज्ञान समझने की क्षमतायें होती हैं। अतः मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं द्वारा इन बालकों का चयन कर उनके लिये अलग पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाना चाहिए। उनके लिए पृथक विद्यालय खोले जाने चाहिए, जिनमें सरल सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम के साथ शिल्प, मैकेनिकल, शिक्षा, कृषि, बागवानी, कढ़ाई एवं सिलाई आदि की शिक्षा होनी चाहिए। यद्यपि यह भारत जैसे देश के लिए असम्भव है, फिर भी यदि प्रयास किया जाय तो श्रेयस्कर होगा। बालकों के समान पाठ्यक्रम, समान शिक्षा का सिद्धान्त अमनोवैज्ञानिक है।

30. स्वास्थ्य का गठन भी शिक्षा का एक अंग है। इसके लिए विद्यालय में व्यायाम शिक्षक भी नियुक्त होते हैं और शिक्षण में शारीरिक शिक्षा के लिए घण्टे भी आवंटित होते हैं परन्तु वस्तुतः विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा का पक्ष अपेक्षित रहता है। विद्यालय में खेल–कूद के उपकरणों की भी समुचित व्यवस्था नहीं रहती है। उत्तम स्वास्थ्य के बिना उत्तम शिक्षा और उत्तम नागरिकता

नहीं उत्पन्न हो सकती है। राष्ट्र के विकास के नागरिकों के उत्तम स्वास्थ्य का होना अपरिहार्य तत्व है।

शोध एवं भावी विकास के लिए सुझाव :-

1. बालक के सर्वांगीण विकास के लिए समाज का कर्तव्य है कि वह स्कूलों की स्थापना करे। वहाँ उस वातावरण का सृजन करें जिससे स्कूलों में रहकर बालक, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास करें।
2. जूनियर हाईस्कूलों की वर्तमान काल में कोई सार्थकता नहीं है। इन विद्यालयों के भवनों का विकास कर उन्हें हाईस्कूल स्तर तक बनाया जाय।
3. जिन हाईस्कूलों अथवा इण्टरमीडिएट कालेजों का वार्षिक परीक्षाफल 45 प्रतिशत से कम हो, उन्हें अनुदान न दिया जाय।
4. जनपद स्तर पर एक सर्वेक्षण इकाई की स्थापना की जाय जो विभिन्न स्तरीय विद्यालयों की गुणवत्ता का सर्वेक्षण करें और इसके आधार पर उन विद्यालयों को अनुदान राशि में बढ़ोत्तरी या घटोत्तरी की जाय।
5. सबको नियमित करने पर बल दिया जाय।
6. विद्यालयों में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के सुचारु संचालन की व्यवस्था की जानी चाहिए।
7. जिन विद्यालयों में विज्ञान, कृषि आदि के अध्ययन के लिए समुचित उपकरण न हों उन्हें उन विषयों की मान्यता न प्रदान की जाय।

8. जनपद में व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा का अधिक से अधिक प्रावधान किया जाय ताकि आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए भी इस प्रकार की शिक्षा सुलभ हो।

9. अध्यापकों की नियुक्ति के लिए जो निर्धारित मापदण्ड हैं वे बहुत उपयोगी नहीं सिद्ध हुए हैं। इसके लिए एक समुचित मापदण्ड का निर्धारण किया जाय।

10. अन्तिम सुझाव यह है कि जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है कि जनपद में उद्योगों के विस्तार के द्वारा आर्थिक विकास में योगदान होना अति आवश्यक है ताकि सामाजिक एवं आर्थिक दोनों ही स्तरों पर जन सामान्य समृद्ध होकर शिक्षा के संचालक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार के विकासों में योगदान कर सकें।

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध के आधार पर भविष्य में शोध हेतु निम्नलिखित शोध शीर्षक लिये जा सकते हैं-

1. स्वतन्त्रता के पश्चात् जौनपुर जनपद में छात्रों और छात्राओं की शैक्षिक प्रगति का एक अध्ययन।
2. स्वतन्त्रता के पश्चात जौनपुर जनपद में शैक्षणिक संस्थाओं के क्रमिक विकास का एक अध्ययन।
3. स्वतन्त्रता के पश्चात जौनपुर जनपद में अनुसूचित जाति के लोगों की शैक्षिक प्रगति का एक अध्ययन।
4. स्वतन्त्रता के पश्चात जौनपुर जनपद में सामान्य तथा पिछड़ी जाति के लोगों की शैक्षिक का एक अध्ययन।

5. स्वतन्त्रता के पश्चात जौनपुर जनपद में तकनीकी शिक्षा के विकास का एक अध्ययन।

6. स्वतन्त्रता के पश्चात जौनपुर जनपद में पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति के लोगों की शैक्षिक प्रगति का एक अध्ययन।

7. स्वतन्त्रता के पश्चात जौनपुर जनपद में छात्राओं की शैक्षिक प्रगति का एक अध्ययन।

शैक्षिक महत्व-

प्रस्तुत अध्ययन के निष्कर्षों से स्पष्ट है कि जनपद के माध्यमिक विद्यालयों की दशा शोचनीय है। विद्यालय में शैक्षिक उपकरणों का अभाव, अपर्याप्त भवन, छात्रों और अध्यापकों की संख्या का असन्तुलित अनुपात आदि विसंगतियों के कारण विद्यालय का वातावरण छात्रों के लिए अनाकर्षक होता है। ये सरकारी विद्यालय छात्रों और अभिभावकों को सन्तुष्ट नहीं कर पाते।

माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था और अनुशासन अच्छा नहीं है। अधिकांश विद्यालयों में मध्याह्न–अवकाश के बाद कक्षायें खाली हो जाती हैं और शिक्षण बाधित होता है। शोध के निष्कर्ष से स्पष्ट है कि उपयुक्त शिक्षण के अभाव में छात्र परीक्षा के समय आत्मबल खो देते हैं और नकल के सहारे परीक्षा उत्तीर्ण करने की सोचते हैं। छात्रों की इस प्रवृत्ति का कुछ अध्यापक अनुचित लाभ उठाते हैं। परीक्षा केन्द्रों पर आदर्शों के प्रचेता शिक्षक मर्यादा की सभी सीमाओं का उल्लंघन कर नकल व्यवसाय में लिप्त हो जाते हैं। कहीं

प्रधानाचार्य, शिक्षक, प्रबन्धक और अभिभावक सभी की मिलीभगत से छात्रों से पैसा वसूलकर उत्तीर्ण कराने का ठेका लिया जाता है। इसके लिए परीक्षार्थियों से परीक्षा पूर्व ही एक मुश्त नकद धनराशि वसूल कर ली जाती है। बहुत से परीक्षा केन्द्र परीक्षा उत्तीर्ण कराने के लिए अन्तर्जनपदीय परीक्षा केन्द्र के रूप में कुख्यात हैं। नकल की प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त नियम बनाये है, फिर भी पूर्ण नियन्त्रण नहीं हो पा रहा है।

निष्कर्षों से ज्ञात होता है कि प्रचलित शिक्षा पद्धति छात्रों को एक संगणक मानकर चल रही है, जिसके मस्तिष्क में सूचनाओं, तथ्यों और विषयवस्तु का संग्रह कर देना ही लक्ष्य रह गया है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की प्राचीन अवधारणा अब पीछे छूट गई है।

छात्रों में नैतिक चरित्र का विकास और उत्तम स्वास्थ्य का निर्माण अब शिक्षा में अतीत की कहानी बन गई है। विद्यालयों में खेल–कूद, व्यायाम तथा संस्कृति कार्यक्रम अपेक्षित हो गये हैं, जो अनुशासन और भावात्मक परिष्कार के लिए उपयोगी थे। शिक्षा से बौद्धिक विकास अवश्य हो रहा है, किन्तु छात्रों का भाव पक्ष संकीर्ण हो रहा है। शिक्षा का लक्ष्य नौकरी और अर्थोपार्जन ही रह गया है।

बालिकाओं की शिक्षा में भी विकास हुआ है। नगरों में ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है। समाज का उच्च और मध्यम वर्ग बालिका शिक्षा को उतना ही महत्व देता है, जितना बालकों की शिक्षा को युगों से दबी, सहमी और आत्महीनता की

ग्रन्थि से कुण्ठित बालिकायें शिक्षा में विशेष रूचि ले रही हैं। बालिकाओं का उत्तीर्णता प्रतिशत बालकों की उत्तीर्णता प्रतिशत से अधिक रहता है। यहाँ तक कि मेरिट लिस्ट में भी छात्रायें स्थान पा रही हैं, किन्तु निम्न वर्ग में बालिका शिक्षा के प्रति तनिक भी जागृति नहीं आई। इसका मुख्य कारण उस वर्ग का आर्थिक पिछड़ापन ही है। जनपद के रूढ़िवादी समाज को देखते हुए बालिका शिक्षा प्रगति सराहनीय है, फिर भी संख्या के अनुपात में बालिका विद्यालयों की संख्या अपर्याप्त है।

अध्ययन से प्रतीत होता है कि अन्य क्षेत्रों की भाँति शिक्षा में भी भ्रष्टाचार का दानव अपने कदम बढ़ा रहा है। जहाँ पहले उदार मना लोग शिक्षालय खोलना एक पुनीत कार्य समझते थे, अपनी सम्पत्ति लगाकर और जनता से चन्दा इकट्ठा कर विद्यालय चलाते थे, वहीं कतिपय स्वार्थी शिक्षा माफिया शिक्षा को व्यवसाय बनाये हुए हैं। वे अच्छी शिक्षा की ओट में छात्रों से मनमाना शिक्षा शुल्क वसूल करते हैं। यद्यपि प्रशासन इनकी गतिविधियों से अनभिज्ञ नहीं है, किन्तु प्रजातन्त्र की राजनीति के चलते उन्हें नेताओं का वरदहस्त प्राप्त होता है, सरकार को उनके आय–व्यय का निरीक्षण कर उनकी निरंकुशता पर अंकुश लगाना चाहिए।

जनपद जौनपुर की भूमि उर्वर है और फल–सब्जियों के उत्पादन की प्रबल सम्भावनायें हैं। कृषि उत्पादों से निर्मित होने वाले संस्करण जेली, जैम, सांस, अचार बनाने आदि के उद्योग यह फलीभूत हो सकते हैं। सरकार को इस प्रकार के औद्योगिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए।